out getting their consent to be transported and charges had been paid even for non-utilisation of the services of these buses ; and

(d) if so, the steps which Government had taken to fix the responsibility of the persons concerned for non-recurrence of such unscrupulous action ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) An expenditure of about Rs.2,838.00 was incurred for serving one meal at the railway station, at the time of commencement of their return journey, to the refugees who had squatted in front of Jaisalmer House and the Prime Minister's residence during 1968-69.

(b) A sum of Rs.6,316.50 was paid to the Delhi Transport Undertaking on account of the buses hired for transportation of the refugees mentioned above to the railway station.

(c) Buses were hired not every day, but only on specific days, after obtaining the consent of the refugees to move to the Railway Station. However, on a few occasions, the migrants changed their mind at the last moment, after the buses had arrived ; in such cases, the minimum hire charges had to be paid to the Delhi Transport Undertaking.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजन आदिवासियों के लिये स्थानों का आरक्षण

8111. **श्री रामसिंह अयरवाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम में हरिजन आदिवासियों के लिये कोई स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि आरक्षण किया गया है; तो कितने प्रतिशत आरक्षित पद भरे गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम के भर्ती नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अभ्यार्थियों के लिये पदों के आरक्षण की व्यवस्था है।

(ख) 51 प्रतिशत।

यह कमी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उचित अभ्यार्थियों की अनुपलब्धि के कारण है। अतः रिक्त स्थान वर्ष प्रति वर्ष आगे ले जाये जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

सागर जिले में कृषि कालेज खोलना

8112. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सागर जिले की खुराई तहसील एक कृषि केन्द्र है और कृषि में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार सागर जिले में एक कृषि कालेज स्थापित करने का प्रयास करेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि वहाँ एक कृषि कालेज खोल दिया जाय; तो उससे प्राकृतिक जल, तकनीकी शिक्षा में प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है और बीड़ी उद्योगपतियों का एकाधिकार समाप्त किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो वहाँ कृषि कालेज स्थापित करने में सरकार को क्या अड़चनें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) सागर जिले की खुराई तहसील की भूमि काफी उर्वर तथा कृषि योग्य है। परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि सागर में कृषि महा-

विद्यालय न होने के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(ख) मध्य प्रदेश में मौजूदा कृषि महाविद्यालयों से पास करे हुए अधिशेष कृषि स्नातकों को दृष्टिगत रखते हुए सागर में एक नया कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए न तो सरकार की और न ही जबलपुर स्थित कृषि विश्व विद्यालय की कोई योजना है।

(ग) जी नहीं। यह अनुमान लगा लेना ठीक नहीं है कि सागर में स्थानीय कृषि महाविद्यालय खोलने से प्राकृतिक जल प्राप्त करने में या बीड़ी उद्योगपतियों का एकाधिकार समाप्त करने में सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य में प्रशिक्षित तकनीकी कार्मिक पहले ही अधिशेष हैं।

(घ) भाग (ख) और (ग) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

OBJECTION BY M. PS. OF CONGRESS (R) FOR SMALL COVERAGE BY A. I. R.

8113. **Shri Bedabrata Barua** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament belonging to Congress (R) have objected to the very small coverage given to the party by the All India Radio in a meeting of the Consultative Committee of his Ministry,

(b) whether any step has been taken to enquire why this had happened ; and

(c) whether steps have been taken to correct this ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. The complaint was that they were not getting as much coverage on All India Radio as Members of the Opposition Parties were.

(b) and (c). All India Radio always tries to provide a balanced coverage to the proceedings of Parliament in its news bulletins and two commentaries. 'Today-in-Parliament' and 'Sansad Sameeksha'. Names are noticed on the basis of the proceedings of the House, their news value and the total space available in a particular bulletin.

TELEPHONE DUES OUTSTANDING UPTO 31ST MARCH, 1970

8114. **Shri Gadilingana Gowd** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the approximate amount due to be recovered against the telephone charges upto the 31st March, 1970 ; and

(b) the steps taken by Government to recover these dues at the earliest ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting, and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Information for the period upto 31st March, 1970 is not available as yet. As on 1st November, 1969, a sum of Rs.647.36 lakhs was outstanding in respect of bills issued upto 31st July, 1969.

(b) Steps, such as, personal contact and correspondence with subscribers, disconnection of telephones and finally legal action, where necessary, are taken with a view to recovering the dues.

संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बीज उत्पादन परियोजन में प्रगति।

8115. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बीज उत्पादन परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त तराई बीज विकास परियोजना के अन्तर्गत, 1969-70 के दौरान 18,304 एकड़ भूमि में बीज का